



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25092025-266388  
CG-DL-E-25092025-266388

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 259]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 24, 2025/आश्विन 2, 1947

No. 259]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 24, 2025/ASVINA 2, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

[व्यापार उपचार महानिदेशालय]

जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2025

मामला संख्या एडी(एसएसआर) -10/2025

**विषय:** चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) मिश्रणों” के आयात के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत।

1. फा. सं. 7/17/2025 - डीजीटीआर: समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) और समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क और (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आंकलन और संग्रहण और क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे “नियमावली” भी कहा गया है) के संबंध में, एसआरएफ लिमिटेड (जिसे आगे 'आवेदक' कहा गया है) ने चीन जन.गण. (जिसे आगे 'संबद्ध देश' कहा गया) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी)

मिश्रणों (जिसे आगे 'विचाराधीन उत्पाद' अथवा 'संबद्ध वस्तु' कहा गया है) के आयात पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे 'प्राधिकारी' कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

2. इस अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार, लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि उसे पहले ही वापस न ले लिया जाए, ऐसे लगाए जाने की तिथि से पाँच वर्ष की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होगा, और प्राधिकारी को यह समीक्षा करनी होगी कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन या क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना है। इसके अनुसार, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करनी होगी कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

#### क. पिछली जांच की पृष्ठभूमि

3. संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयात से संबंधित मूल पाटनरोधी जांच 30 सितंबर 2020 को शुरू की गई थी। विस्तृत जांच के अनुसरण में, प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम संख्या फा. संख्या 06/34/2020-डीजीटीआर दिनांक 27 सितंबर 2021 के तहत पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की। वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या 76/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 22 दिसंबर 2021 के तहत 5 वर्षों की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाया।

#### ख. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)

4. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद मूल जांच में परिभाषित उत्पाद के समान है, जो इस प्रकार है:

*"7. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) मिश्रण" है। 407 और 410 के अलावा सभी मिश्रणों को बाहर रखा गया है।*

*8. एचएफसी मिश्रण रंगहीन, गंधहीन गैस हैं जिनमें केवल हाइड्रोजन, फ्लोरीन और कार्बन होते हैं और इनका उपयोग आवासीय और वाणिज्यिक एयर कंडीशनिंग प्रणालियों में निम्न से मध्यम तापमान वाले रेफ्रिजरेट के रूप में किया जाता है। इनके दो प्रमुख अंतिम उपयोग आवासीय एयर कंडीशनिंग और हीट पंप, वाणिज्यिक एयर कंडीशनिंग, वाणिज्यिक प्रशीतन, परिवहन प्रशीतन और प्रक्रिया प्रशीतन, जैसे खाद्य प्रसंस्करण और रासायनिक निर्माण में होते हैं। जाँच के उद्देश्य से एचएफसी मिश्रणों को एक ही वस्तु माना जाता है।*

5. विचाराधीन उत्पाद को मूल जाँच में सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 38 के अंतर्गत उपशीर्ष 3824 78 00 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। मार्च 2022 से प्रशुल्क वर्गीकरण में परिवर्तन करके उपशीर्ष 3827 63 00 और 3827 64 00 कर दिया गया है। सीमा प्रशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
6. वर्तमान आवेदन एक निर्णायक समीक्षा जाँच होने के कारण, विचाराधीन उत्पाद मूल अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में परिभाषित के अनुसार ही बना हुआ है।

7. आवेदक ने पैकड और अनपैकड को पीसीएन पद्धति के रूप में मानने का प्रस्ताव दिया है। आयात केवल अनपैकड रूप में हुआ है।

**ग. समान वस्तु**

8. आवेदक ने दावा किया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से निर्यातित उत्पाद में कोई अधिक अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों एवं उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन, तथा वस्तुओं के प्रशुल्क वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थानापन्न योग्य हैं और उपभोक्ताओं द्वारा इनका उपयोग एक-दूसरे के स्थान पर किया जाता है। वर्तमान आवेदन पाटनरोधी शुल्क के निरंतर अधिरोपण हेतु निर्णायक समीक्षा जाँच के लिए है। समान वस्तु के मुद्दे की जाँच प्राधिकारी द्वारा मूल जाँच में भी पहले ही की जा चुकी है। आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद, संबद्ध देश से उत्पादित और आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।

**घ. घरेलू उद्योग और आधार**

9. आवेदन एसआरएफ लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने प्रमाणित किया है कि उसने संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है और न ही वह संबद्ध देश के निर्यातकों या भारत में आयातकों से संबद्ध है।
10. आवेदक के अलावा, भारत में संबद्ध वस्तु के अन्य उत्पादक भी हैं। गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड ने आवेदन का समर्थन किया है। प्राधिकारी ने उत्पादकों को आवेदन प्राप्ति की सूचना भेजी थी। किसी भी उत्पादक ने इस सूचना का उत्तर नहीं दिया है।
11. रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, यह देखा गया है कि आवेदक का उत्पादन भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख अनुपात है। इसके मद्देनजर, और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर, यह देखा गया है कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से घरेलू उद्योग है। यह आवेदन के नियम 5(3) के अनुसार आवश्यक शर्तों को पूरा करता है।

**ड. संबद्ध देश**

12. वर्तमान जाँच में संबद्ध देश चीन जन.गण. है।

**च. जाँच की अवधि**

13. जाँच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 (12 महीने) तक है। क्षति जांच की अवधि अप्रैल 2021 - मार्च 2022, अप्रैल 2022 - मार्च 2023, अप्रैल 2023 - मार्च 2024 और जाँच की अवधि है।

**छ. कथित पाटन का आधार**

**i. सामान्य मूल्य**

14. आवेदक ने चीन के आरोहण नयाचार के अनुच्छेद 15(क) (i) का हवाला दिया है और उस पर भरोसा किया है और दावा किया है कि चीन जन.गण. को एक गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और चीन जन.गण. के उत्पादकों को यह दर्शाने का निदेश दिया जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाज़ार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं। जब तक चीन जन.गण. के उत्पादक यह नहीं दर्शाते हैं कि ऐसी बाज़ार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं, तब तक उनका सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।
15. आवेदक ने अनुरोध किया है कि बाज़ार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागत और कीमत से संबंधित आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। आवेदक ने बाज़ार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश से भारत सहित किसी अन्य देश को उत्पाद की निर्यात कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। आवेदक ने यूरोपीय संघ से आयात कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है, जिसे निवल कारखानागत स्तर पर समायोजित किया गया है। आवेदक ने भारत में भुगतान की गई और देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य की पूर्ति भी की है।
16. जांच की शुरुआत करने के प्रयोजनार्थ, विचाराधीन उत्पाद का सामान्य मूल्य भारत में उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित किया गया है, जिसे बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों तथा उचित लाभ को जोड़कर विधिवत समायोजित किया गया है।

**ii. निर्यात कीमत**

17. विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत, डीजी प्रणाली के लेन-देन-वार आयात आंकड़ों में दर्शाए गई सीआईएफ कीमत को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, पोर्ट व्यय, अंतर्देशीय माल ढुलाई व्यय और ऋण लागत के लिए समायोजन का दावा किया गया है।

**iii. पाटन मार्जिन**

18. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना द्वार स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह सिद्ध होता है कि संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम स्तर से ऊपर है, बल्कि अधिक भी है। चूँकि वर्तमान जाँच एक निर्णायक समीक्षा जाँच है, इसलिए प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों से सूचना और साक्ष्य प्राप्त होने के बाद पाटन की संभावना का भी निर्धारण करेंगे।

**ज. क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना और कारणात्मक संबंध**

19. आवेदक ने उपायों के समाप्त होने की स्थिति में क्षति की संभावना के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आवेदक ने दावा किया है कि उपायों के लागू होने और आर-125 के निर्यात में वृद्धि के कारण पाटित आयातों में कमी आई है, लेकिन वे घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से नीचे बने हुए हैं। आवेदक ने क्षति की संभावना के अपने

दावे के समर्थन में अधिशेष क्षमता, तृतीय देश के उपायों और तृतीय देश की कीमत विश्लेषण की जानकारी भी प्रदान की है। आवेदक द्वारा प्रदान की गई जानकारी, प्रथम दृष्टया, संबद्ध देश से पाटन जारी रहने और पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना दर्शाती है।

### झ. निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरुआत

20. आवेदक के विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर, तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य के आधार पर, जो पाटन और क्षति के जारी रहने/पुनरावृत्ति की संभावना को प्रमाणित करता है, स्वयं को संतुष्ट करते हुए, तथा नियमावली के नियम 23 (आईबी) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार, प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में लागू शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने तथा यह जाँच करने के लिए कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना है, एक निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरुआत करते हैं।

### ञ. प्रक्रिया

21. वर्तमान जाँच के लिए नियमावली के नियम 6 में दिए गए सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

### ट. सूचना प्रस्तुत करना

22. सभी पत्राचार निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पते [jd12-dgtr@gov.in](mailto:jd12-dgtr@gov.in) और [ad12-dgtr@gov.in](mailto:ad12-dgtr@gov.in) पर भेजी जानी चाहिए और उसकी एक प्रति [dir15-dgtr@gov.in](mailto:dir15-dgtr@gov.in) और [consultant-dgtr@nic.in](mailto:consultant-dgtr@nic.in) को भेजी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का विस्तृत भाग खोज योग्य पीडीएफ/एमएस वर्ड प्रारूप में हो और आंकड़ा फ़ाइलें एमएस एक्सेल प्रारूप में हों।
23. संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, और भारत में उन आयातकों और प्रयोक्ताओं को, जो संबद्ध वस्तुओं से जुड़े हुए हैं, अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर सभी संगत जानकारी प्रस्तुत कर सकें। ऐसी सभी जानकारी इस जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा यथा-निर्धारित रूप में और तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए।
24. कोई भी अन्य हितबद्ध पक्षकार इस जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से, इस जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर, वर्तमान जाँच से संबंधित अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
25. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को उसका एक अगोपनीय रूपांतर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।
26. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट ([dgtr-india@gov.in](mailto:dgtr-india@gov.in)) नियमित रूप से देखते रहें ताकि वे जानकारी और जाँच से संबंधित आगे की प्रक्रियाओं से अद्यतन और अवगत रहें।

## ठ. समय सीमा

27. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईमेल पते [jd12-dgtr@gov.in](mailto:jd12-dgtr@gov.in) और [ad12-dgtr@gov.in](mailto:ad12-dgtr@gov.in) पर भेजी जानी चाहिए और उसकी एक प्रति [dir15-dgtr@gov.in](mailto:dir15-dgtr@gov.in) और [consultant-dgtr@nic.in](mailto:consultant-dgtr@nic.in) को भेजी जानी चाहिए। तथापि यह नोट किया जाए कि उक्त नियमावली की व्याख्या के संबंध में सूचना और अन्य दस्तावेजों की मांग करने वाले नोटिस को उस तिथि से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त किया गया माना जाना चाहिए जिस तिथि को उसे प्राधिकारी द्वारा भेजा गया था अथवा निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को परिचालित किया गया था। यदि कोई सूचना निर्धारित समय के भीतर प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और नियमावली के अनुसार अपने जांच परिणाम रिकॉर्ड कर सकते हैं।
28. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपनी रुचि (हित की प्रकृति सहित) से अवगत कराएं और इस अधिसूचना में निर्धारित उपरोक्त समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली के उत्तर दायर करें।
29. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध दायर करने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है, उसे पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार ऐसे समय विस्तार के लिए पर्याप्त कारण दर्शाना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाना चाहिए।

## ड. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

30. जहां वर्तमान जांच में कोई पक्षकार गोपनीय अनुरोध करता है अथवा प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर सूचना देता है, वहां उस पक्षकार के लिए यह अपेक्षित है कि वे नियमावली के नियम 7(2) के संदर्भ में और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय रूपांतर साथ-साथ प्रस्तुत करें।
31. ये अनुरोध प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर “गोपनीय” अथवा “अगोपनीय” स्पष्ट रूप से चिह्नित होने चाहिए। प्राधिकारी को ऐसे चिन्हों के बिना किया गया कोई भी अनुरोध “अगोपनीय” सूचना माना जाएगा, और प्राधिकारी उन अनुरोधों का निरीक्षण करने के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
32. गोपनीय रूपांतर में वे सभी जानकारी शामिल होनी चाहिए जो स्वभावतः गोपनीय हो, और/या अन्य जानकारी, जिसके बारे में ऐसी जानकारी का प्रदाता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी जानकारी जिसके स्वभावतः गोपनीय होने का दावा किया गया हो, या जिस जानकारी की गोपनीयता का दावा अन्य कारणों से किया गया हो, उसके लिए सूचना प्रदाता को दी गई जानकारी के साथ यह उचित कारण बताना होगा कि ऐसी जानकारी का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता।
33. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत जानकारी का अगोपनीय रूपांतर गोपनीय रूपांतर की एक प्रति होनी चाहिए, जिसमें गोपनीय जानकारी को अधिमानतः अनुक्रमित किया जाना चाहिए या जहाँ (अनुक्रमण संभव न हो), वहाँ रिक्त स्थान दिया जाना चाहिए, और ऐसी जानकारी को उस जानकारी के आधार पर उचित और पर्याप्त रूप से संक्षेपित किया जाना चाहिए जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है।
34. अगोपनीय सारांश में गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना के सार को उचित रूप से समझने के लिए पर्याप्त विवरण होना चाहिए। हालाँकि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संकेत दे सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, और प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए इस बात का विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है।

35. हितबद्ध पक्षकार, अनुरोधों के अगोपनीय रूपांतर के परिचालन की तिथि से 7 दिनों के भीतर, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा किए गए गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं।
36. गोपनीयता के दावे पर नियमावली के नियम 7 के अनुसार, बिना किसी सार्थक अगोपनीय रूपांतर या पर्याप्त एवं समुचित कारण कथन के, और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
37. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जाँच के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध उचित है या यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या संक्षिप्त रूप में इसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना को अस्वीकार कर सकते हैं।
38. प्राधिकारी, प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट और स्वीकार होने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना किसी भी पक्षकार को इसका प्रकटन नहीं करेंगे।

**ढ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**

39. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और साथ ही उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि सभी अन्य हितबद्ध पक्षकार अपने अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर ईमेल से भेजें।

**ण. असहयोग**

40. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उपयुक्त अवधि के भीतर अथवा इस जांच संबंधी अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर आवश्यक सूचना तक पहुंच से इंकार करता है अथवा अन्यथा नहीं देता है अथवा जांच में काफी बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं तथा अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणामों को दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं, जिन्हें वह उपयुक्त मानें।

सिद्धार्थ महाजन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

(Department of Commerce)

**[DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES]**

**INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th September, 2025

**CASE No. AD (SSR)- 10/2025**

**Subject: Initiation of sunset review investigation concerning imports of “Hydrofluorocarbon (HFC) Blends” originating in or exported from China PR.**

1. **F. No. 7/17/2025 - DGTR:** Having regards to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the ‘Act’) and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the ‘Rules’), SRF Limited (hereinafter referred to as the ‘applicant’) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the ‘Authority’), for initiation of the sunset review investigation of anti-dumping duty on imports of Hydrofluorocarbon (HFC) Blends (hereinafter referred to as the ‘product under consideration’ or ‘subject goods’), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the ‘subject country’).

2. In terms of Section 9A (5) of the Act, the anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition, and the Authority is required to review whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping or injury. In accordance with the same, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

**A. Background of previous investigation.**

3. The original anti-dumping investigation concerning imports of product under consideration from the subject country was initiated on 30<sup>th</sup> September 2020. Pursuant to detailed investigation, the Authority recommended imposition of anti-dumping duty vide final findings no. F. No.06/34/2020-DGTR dated 27<sup>th</sup> September 2021. The Ministry of Finance vide Notification No. 76/2021-Customs (ADD) dated 22<sup>st</sup> December 2021 imposed anti-dumping duties for a period of 5 years.

**B. Product under consideration (PUC).**

4. The product under consideration in the present investigation is same as defined in the original investigation which is as follows:

*“7. The product under consideration in the present investigation is "Hydrofluorocarbon (HFC) Blends. All blends other than 407 and 410 are excluded".*

*8. HFC Blends are colourless, odourless gasses containing only hydrogen, fluorine and carbon and are used as low-to-medium temperature refrigerants in residential and commercial air conditioning systems. The two major end uses are in residential air conditioning and heat pumps, commercial air conditioning, commercial refrigeration, transportation refrigeration, and process refrigeration, e.g., food processing and chemical manufacturing. The HFC Blends are considered as a single article for the purpose of the investigation.”*

5. The product under consideration was classified in the original investigation under Chapter 38 of the Customs Tariff Act, 1975 under subheading 3824 78 00. The tariff classification has undergone a change from March 2022 to subheadings 3827 63 00 and 3827 64 00. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.
6. The present application being a sunset review investigation, the product under consideration remains the same as defined in the original final finding notification.
7. The applicant has proposed to consider packed and unpacked as PCN methodology. The imports have taken place only for the unpacked form.

**C. Like article.**

8. The applicant has claimed that there are no significant difference in the product produced by the applicant and the one exported from the subject country. The product produced by the applicant and imported from the subject country is comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses. product specifications, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The two are



technically and commercially substitutable and are used by consumers interchangeably. The present application is for sunset review investigation for the continued imposition of anti-dumping duty. The issue of like article has already been examined by the Authority in the original investigation as well. The product produced by the applicant is like article to the product under consideration produced and imported from the subject country.

**D. Domestic industry and standing.**

9. The application has been filed by the SRF Limited. The applicant has certified that it has not imported the subject goods nor related to the exporters from the subject country or importers in India.
10. Apart from the applicant, there are other producers of the subject goods in India. Gujarat Fluorochemicals Limited has supported the application. The Authority had sent an intimation to the producers about the receipt of the application. None of the producers have replied to this intimation.
11. As per the evidence available on record, it is seen that the production of the applicant accounts for a major proportion in the domestic production of the like article in India. In view of the same, and based on information available on record, it is seen that the applicant constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules. The application satisfies the requirements of standing in terms of Rule 5(3).

**E. Subject country.**

12. The subject country in the present investigation is China PR.

**F. Period of investigation.**

13. The period of investigation (POI) for the investigation is from 1<sup>st</sup> April 2024 – 31<sup>st</sup> March 2025 (12 months). The injury examination period is April 2021 - March 2022, April 2022 - March 2023, April 2023 – March 2024 and the period of investigation.

**G. Basis of alleged dumping.**

**i. Normal value.**

14. The applicant has cited and relied upon Article 15(a) (i) of China's Accession Protocol and has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and that producers from China PR should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry with regard to the production and sales of the product under consideration. Unless the producers from China PR show that such market economy conditions prevail, their normal value should be determined in accordance with Para 7 and 8 of Annexure-I to the Anti-Dumping Rules, 1995.
15. The applicant has submitted that data relating to cost and price in market economy third country is not available. The applicant has claimed normal value based on the export price of the product from a market economy third country to any other country, including India. The applicant has claimed normal value based on the import price from European Union adjusted to arrive at net ex-factory level. The applicant has also supplemented normal value based on the price paid and payable in India.

16. For the purpose of initiation, the normal value for the product under consideration has been determined based on cost of production in India, duly adjusted for addition of selling, general and administrative expenses and reasonable profits.

**ii. Export price**

17. The export price of the product under consideration has been determined by considering the CIF price of the product under consideration as reported in DG Systems transaction wise import data. Adjustments have been claimed for ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses, inland freight expenses and credit cost.

**iii. Dumping margin**

18. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* establishes that the dumping margin with respect to the product under consideration imported from the subject country is not only above the *de minimis* level but is also significant. Since the present investigation is a sunset review investigation, the Authority shall also determine likelihood of dumping after receipt of information and evidence from the interested parties.

**H. Likelihood of continuation or recurrence of injury and causal link**

19. The applicant has provided *prima facie* evidence with respect to likelihood of injury in the event of cessation of measures. The applicant has claimed that the dumped imports have declined because of imposition of measures and increase in the exports of R-125 but have continued to remain below the cost of production of the domestic industry. The applicant has also provided information on surplus capacities, third country measures and third country price analysis in support of its claim of likelihood of injury. The information provided by the applicant, *prima facie*, shows continuation of dumping from the subject country and likelihood of injury to the domestic industry in case of cessation of the anti-dumping duty.

**I. Initiation of sunset review investigation.**

20. On the basis of the duly substantiated application of the applicant, and having satisfied itself on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the applicant, substantiating the likelihood of continuation/ recurrence of dumping and injury, and in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 (IB) of the Rules, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

**J. Procedure.**

21. Principles, as given in Rule 6 of the Rules, will be followed for the present investigation

**K. Submission of information.**

22. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses [jd12-dgtr@gov.in](mailto:jd12-dgtr@gov.in) and [ad12-dgtr@gov.in](mailto:ad12-dgtr@gov.in) with a copy to [dir15-dgtr@gov.in](mailto:dir15-dgtr@gov.in) and [consultant-dgtr@nic.in](mailto:consultant-dgtr@nic.in). It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.

23. The known producers/exporters in subject country, the government of subject country through its Embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the product under consideration are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.
24. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.
25. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
26. Interested parties are further directed to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies ([dgtr-india@gov.in](mailto:dgtr-india@gov.in)) to stay updated and apprised with the information as well as further processes related to the investigation.

**L. Time limit.**

27. Any information relating to the present investigation should be sent to the Authority via email at email addresses [jd12-dgtr@gov.in](mailto:jd12-dgtr@gov.in) and [ad12-dgtr@gov.in](mailto:ad12-dgtr@gov.in) with a copy to [dir15-dgtr@gov.in](mailto:dir15-dgtr@gov.in) and [consultant-dgtr@nic.in](mailto:consultant-dgtr@nic.in) within 30 days from the date of the receipt of the notice as per the Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rules, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have received within one week from the date on which it was sent by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
28. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification.
29. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6(4) of the AD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

**M. Submission of information on confidential basis.**

30. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.
31. Such submissions must be clearly marked as 'confidential' or 'non-confidential' at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as 'non-confidential' information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.

32. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
33. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
34. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
35. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.
36. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
37. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
38. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

**N. Inspection of public file.**

39. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties.

**O. Non-cooperation.**

40. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

SIDDHARTH MAHAJAN, Designated Authority